Toppersnotes®
Unleash the topper in you

HCS

हरियाणा सिविल सेवा

प्रीलिम्स

हरियाणा लोक सेवा आयोग

भाग - 4

आधुनिक इतिहास

SIERRA INNOVATIONS

विषयसूची

S No.	Chapter Title	Page No.
1	1857 के पूर्व प्रशासन	1
2	1857 का विद्रोह	5
3	ब्रिटिश शासन के तहत अर्थव्यवस्था	11
4	राष्ट्रवाद का जन्म (मध्यम चरण 1885–1905)	21
5	उग्रवादी राष्ट्रवाद का युग चरमपंथी चरण	26
6	जन आंदोलन गांधीवादी युग (1917–1925)	39
7	स्वराज के लिए संघर्ष (1925–1939)	48
8	स्वतंत्रता की ओर (1940–1947)	66
9	महत्वपूर्ण व्यक्ति और घटनाएँ	76
10	ब्रिटिश शासन के खिलाफ लोकप्रिय आंदोलन	87

1 CHAPTER

1857 के पूर्व प्रशासन

- वर्ष 1600 में गठित ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय शासकों के साथ 1611 में पूर्वी तट पर मसूलीपट्टनम (मछलीपट्टनम) और 1612 में पश्चिमी तट पर सूरत में व्यापारिक संबंध स्थापित किये।
- बाद में उन्होंने 1612 में सूरत में और 1616 में मछलीपट्टनम में कारखाने स्थापित किए। बॉम्बे को 1661 में कैथरीन ऑफ ब्रागांज़ा की शादी में दहेज के रूप में पुर्तगाल द्वारा ब्रिटिश क्राउन को सौंपा गया था।
- अंग्रेजों ने भारत में अपने कब्जे वाले क्षेत्रों को प्रांतों के रूप में विभाजित किया,
- जिनमे से तीन बंगाल, बॉम्बे (मुंबई) और मद्रास (चेन्नई) थे ।
- इन प्रान्तों को प्रेसिडेंसी कहा जाता था और प्रत्येक प्रेसिडेंसी का प्रशासन एक गवर्नर द्वारा चलाया जाता था , जिसमें गवर्नर-जनरल सर्वोच्च प्रमुख के रूप में कार्य करता था।

सिविल सेवाएं	➢ इन्हें लॉर्ड कार्नवालिस द्वारा शुरू किया गया । ➢ कंपनी के क्षेत्रों का प्रशासन प्रभावी ढंग से चलाने के लिए सिविल सेवा की शुरुआत की गई। ➢ युवा सिविल सेवकों को प्रशिक्षित करने के लिए लॉर्ड वेलेस्ली ने सन 1800 में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की ➢ चार्टर अधिनियम, 1853 ने सिविल सेवा भर्ती में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को खत्म कर दिया और चयन के लिए खुली प्रतियोगी परीक्षाओं की शुरुआत की गई। प्रारंभ में यह परीक्षा लंदन में आयोजित की जाती थी जिसके कारण बहुत कम भारतीय इस परीक्षा का खर्च उठा पाते थे। ➢ सत्येंद्रनाथ टैगोर (रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई) भारतीय सिविल सेवा (ICS) में शामिल होने वाले पहले भारतीय थे।
पुलिस	➢ 1791 में लॉर्ड कार्नवालिस ने एक स्थायी पुलिस बल का गठन किया और पुलिस अधीक्षक (SP) का पद शुरू किया। ➢ बेंटिक ने SP का पद समाप्त कर दिया और कलेक्टर/मजिस्ट्रेट को उनके अधिकार क्षेत्र में पुलिस बल का प्रमुख बना दिया। ➢ पुलिस अधिनियम, 1861 द्वारा प्रान्तों की पुलिस हेतु दिशानिर्देश प्रस्तुत किए गए।
न्यायपालिका	➢ वारेन हेस्टिंग्स और लॉर्ड कार्नवालिस ने न्यायिक व्यवस्था को व्यवस्थित किया। ➢ जिला स्तर पर सिविल न्यायालय (दीवानी अदालतें) और आपराधिक न्यायालय (फौजदारी अदालतें) स्थापित किए गए। ➢ भारतीय कानूनों को संहिताबद्ध करने के लिए 1833 में एक विधि आयोग का गठन किया गया।

1. बंगाल प्रेसीडेंसी

- बंगाल प्रेसीडेंसी, ब्रिटिश साम्राज्य का एक उपखंड थी।
- पहले आधिकारिक तौर पर फोर्ट विलियम की प्रेसीडेंसी थी, जो बाद में में बंगाल प्रान्त फोर्ट विलियम के आसपास विकसित हुआ कलकत्ता शहर बंगाल प्रेसीडेंसी की राजधानी था।
- कई वर्षों तक बंगाल का गवर्नर भारत का वायसराय भी था और 1911 तक कलकत्ता भारत की राजधानी रहा।
- ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए अन्य यूरोपीय कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा की।
- प्लासी (1757) और बक्सर(1764) युद्ध के बाद, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकांश हिस्से पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था

प्रशासनिक परिवर्तन और स्थायी बंदोबस्त

- प्लासी युद्ध, 1757 ने बंगाल के प्रशाशन में अंग्रेजों के लिए मार्ग प्रशस्त किया ।
- वारेन हेस्टिंग्स ने बंगाल पर ब्रिटिश साम्राज्यवादी शासन को मजबूत किया ।
- लॉर्ड कार्नवालिस ने भूमि पर भूमिधारकों के अधिकारों को स्पष्ट कर उन्हें परिभाषित किया।
- 1793 में लॉर्ड कार्नवालिस ने भू-राजस्व प्रणाली में स्थायी बंदोबस्त लागू किया

2. 1857 तक संवैधानिक, प्रशासनिक और न्यायिक विकास

रेग्युलेटिंग एक्ट, 1773

- अधिनियम के प्रावधान
  - ✓ ‘बंगाल के गवर्नर’ पद को 'अब बंगाल का गवर्नर-जनरल' पद बना दिया गया, एवम् बंगाल के पहले गवर्नर-जनरल या बंगाल के अंतिम गवर्नर- लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे।
  - ✓ गवर्नर-जनरल की सहायता के लिए चार सदस्यों की एक गवर्नर-जनरल परिषद बनाई गई।
  - ✓ बम्बई और मद्रास प्रेसीडेंसी के गवर्नरों को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया।
  - ✓ इसके तहत कलकत्ता (1774) में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया, जिसमें कलकत्ता के फोर्ट विलियम में एक मुख्य न्यायाधीश और तीन अन्य न्यायाधीश थे।
  - ✓ इसने कंपनी के कर्मचारियों के लिए किसी भी प्रकार का निजी व्यापार करने या 'मूल निवासियों' से उपहार या रिश्वत लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया।
  - ✓ निदेशक मंडल (कंपनी का शासी निकाय) को भारत में अपने राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की रिपोर्ट ब्रिटिश सरकार को देना अनिवार्य था।
- संशोधन (1781)
  - ✓ कलकत्ता के भीतर, सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र परिभाषित किया गया, जिसके तहत प्रतिवादी को उसके व्यक्तिगत कानून से प्रशासित करना था।

पिट्स इंडिया एक्ट, 1784

- अधिनियम के प्रावधान
  - ✓ इसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी की राजनीतिक और वाणिज्यिक गतिविधियों को विभाजित किया गया।
  - ✓ 'भारत में ब्रिटिश आधिपत्य' शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया।
  - ✓ राजनीतिक मुद्दों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड(Board of Control) का गठन किया गया
  - ✓ वाणिज्यिक मामलों का प्रबंधन निदेशक मंडल द्वारा किया जाएगा।
  - ✓ सभी नागरिक और सैन्य कार्यों की नियंत्रण बोर्ड द्वारा की जाती थी।
  - ✓ राजस्व की निगरानी भी नियंत्रण बोर्ड द्वारा की जाएगी।

1786 का अधिनियम

- अधिनियम के प्रावधान
  - ✓ इस अधिनियम में कॉर्नवॉलिस की मांग को स्वीकार करके उसे गवर्नर-जनरल तथा कमांडर-इन-चीफ दोनों की शक्तियाँ प्रदान कर दीं गई।
  - ✓ कॉर्नवॉलिस को परिषद के निर्णय को रद्द करने की अनुमति दी गई, बशर्ते निर्णय की जिम्मेदारी उसकी हो।
  - ✓ बाद में यह प्रावधान सभी गवर्नर जनरलों तक बढ़ा दिया गया।

चार्टर अधिनियम, 1793

- अधिनियम के प्रावधान
  - ✓ इस अधिनियम के तहत भारत में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को अगले 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया।
  - ✓ कंपनी को भारत में व्यापार करने के लिए व्यक्तियों के साथ-साथ कंपनी के कर्मचारियों को भी लाइसेंस देने का अधिकार दिया गया।
  - ✓ गवर्नर-जनरल, गवर्नरो और कमांडर-इन-चीफ की नियुक्ति के लिए शाही अनुमोदन (सम्राट की सहमती) अनिवार्य था।

चार्टर अधिनियम, 1813

- अधिनियम के प्रावधान
  - ✓ भारत में कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो गया, लेकिन चीन से व्यापार एवम् चाय के व्यापार पर उसका एकाधिकार बना रहा।
  - ✓ कंपनी के शेयरधारकों को भारत के राजस्व से 10.5% लाभांश दिया जाने लगा।
  - ✓ कंपनी को क्राउन की संप्रभुता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, 20 वर्षों तक भारत के क्षेत्रों और राजस्व पर नियंत्रण बनाए रखने का अधिकार दिया गया।
  - ✓ भारत में पहली बार ब्रिटिश क्षेत्रों की संवैधानिक स्थिति को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया।
  - ✓ नियंत्रण बोर्ड की शक्तियों का विस्तार कर दिया गया।
  - ✓ भारत के मूल निवासियों हेतु साहित्य, शिक्षा और विज्ञान के पुनरुद्धार, संवर्धन और प्रोत्साहन के लिए प्रति वर्ष एक लाख रुपये की धनराशि का प्रावधान किया गया।
  - ✓ ईसाई मिशनरियों (धर्म प्रचारकों) को भारत आने और अपने धर्म का प्रचार करने की अनुमति दी गई।

चार्टर अधिनियम, 1833

- अधिनियम के प्रावधान
  - ✓ कंपनी का अधिकार 20 वर्षों के लियें बढ़ा दिया गया , परन्तु यह निश्चित किया गया की भारतीय क्षेत्रों पर शासन ब्रिटिश सम्राट के नाम से किया जाएगा
  - ✓ चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार भी समाप्त कर दिया गया।
  - ✓ यूरोपीय का भारत में आप्रवासन (immigration) और उनके द्वारा संपत्ति अधिग्रहण पर सभी प्रतिबंध हटा दिए गए।
  - ✓ भारत में सरकार के वित्तीय, विधायी और प्रशासनिक केंद्रीकरण की परिकल्पना की गई थी:
    - प्रशासनिक: गवर्नर-जनरल को कंपनी के सभी नागरिक और सैन्य मामलों के अधीक्षण, नियंत्रण और निर्देशन करने की शक्ति दी गई।
    - बंगाल, मद्रास, बम्बई और अन्य सभी क्षेत्रों को गवर्नर-जनरल के पूर्ण नियंत्रण में रखा गया।
    - वित्तीय: सभी राजस्व गवर्नर-जनरल के अधिकार के तहत जुटाए जाने थे और उसे ही इनके व्यय का अधिकार भी होगा
    - विधायी : मद्रास और बम्बई सरकार की विधायी शक्तियाँ समाप्त कर दी गई और उन्हें ऐसी कानूनी परियोजनाओं जिन्हें वे समीचीन समझते हो को गवर्नर-जनरल के समक्ष प्रस्तावित करने का अधिकार छोड़ दिया गया,
  - ✓ भारतीय कानूनों को संहिताबद्ध और एकीकृत किया जाना था। गवर्नर-जनरल की परिषद में विधि विशेषज्ञ के रूप में एक सदस्य जोड़ा गया
  - ✓ भारत में दास प्रथा को गैर क़ानूनी घोषित कर अंततः उसे समाप्त करने के लिए गवर्नर-जनरल से कदम उठाने का आग्रह किया गया। (दास प्रथा को 1843 में समाप्त कर दिया गया।)

1853 का चार्टर अधिनियम

- अधिनियम के प्रावधान
  - ✓ कंपनी का क्षेत्रों पर नियंत्रण जारी रहेगा, जब तक संसद कुछ और प्रावधान न करे
  - ✓ निदेशक मंडल के सदस्यों की संख्या घटाकर 18 कर दी गई।
  - ✓ सेवाओं/नियुक्तियों पर कंपनी का संरक्षण समाप्त कर दिया गया - सेवाओं को अब प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु खोल दिया गया।
  - ✓ विधि विशेषज्ञ को गवर्नर-जनरल की कार्यकारी परिषद का पूर्ण सदस्य बनाया गया।
  - ✓ भारत में ब्रिटिश सरकार के कार्यकारी और विधायी कार्यों का विभाजन आगे बढ़ाया गया साथ ही विधायी उद्देश्यों के लिए छह अतिरिक्त सदस्यों को शामिल किया गया। भारतीय विधानमंडल में स्थानीय प्रतिनिधित्व की शुरुआत की गई एवं विधायी शाखा को भारतीय विधान परिषद कहा गया।
  - ✓ हालांकि, किसी कानून को लागू करने के लिए गवर्नर-जनरल की सहमति आवश्यक थी, और गवर्नर-जनरल विधान परिषद के किसी भी विधेयक को वीटो कर सकते थे।

2 CHAPTER 1857 का विद्रोह

1857 के विद्रोह के कारण

1. राजनीतिक कारण:

- ब्रिटिश सरकार की प्रत्यक्ष विलय/साम्राज्यवादी नीति और व्यपगत सिद्धांत के तहत राज्यों को अधिगृहित कर लेना। रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र को झांसी के सिंहासन पर बैठने की अनुमति नहीं दी गई।
- 1849 में, लॉर्ड डलहौज़ी ने घोषणा की कि बहादुर शाह II के उत्तराधिकारी को लाल किला छोड़ना होगा।
- लॉर्ड डलहौज़ी ने अवध को कुप्रशासन के बहाने अपने कब्जे में ले लिया, जिससे हजारों रईस, अधिकारी, सेवक और सैनिक बेरोजगार हो गए।

Note: व्यपगत का सिद्धांत

- यह ब्रिटिश सरकार की हड़प नीति थी, जिसके तहत दत्तक पुत्र को सिंहासन पर बैठने की अनुमति नहीं दी जाती थी। इस नीति के तहत निम्न राज्यों को हड़प लिया - सतारा (1848), संबलपुर (1850), उदयपुर (1852), झांसी (1853), नागपुर (1854)।
- बरार और अवध को कुशासन के बहाने अधिगृहित कर लिया ।

2. आर्थिक कारण:

- भारी कराधान: स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी जैसी भूमि राजस्व व्यवस्थाओं के तहत किसानों पर अत्यधिक भूमि कर का बोझ डाला गया।
- भूमि सुधार: पारंपरिक जमींदारी अधिकारों को समाप्त करने से ग्रामीण समाज में अस्थिरता पैदा हुई।
- कृषि का व्यावसायीकरण: नकदी फसलों की ओर रूख करने से खाद्य आपूर्ति और आजीविका प्रभावित हुई।
- औद्योगिक पतन: ब्रिटिश नीतियों के कारण पारंपरिक हस्तशिल्प और उद्योगों का पतन हुआ।
  - ✓ व्यापार नीतियाँ: ब्रिटिश शोषणकारी व्यापार नीतियों ने भारतीय कारीगरों की अपेक्षा ब्रिटिश निर्माताओं को लाभ प्रदान किया।
- अकाल और गरीबी: अकाल की बारंबारता और आर्थिक कठिनाई ने जनता के बीच असंतोष को बढ़ावा दिया।

3. प्रशासनिक कारण:

- कंपनी के प्रशासन में मुख्यतः पुलिस, छोटे अधिकारियों और निचली अदालतों में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार था, जिससे जनता में भारी असंतोष पैदा हुआ।
- भारतीयों को सभी श्रेष्ठ और उच्च वेतन वाली नौकरियों से बाहर रखा गया।

4. सामाजिक-धार्मिक कारण:

- लेक्स लोकी अधिनियम, 1850 के साथ भारत में तेजी से फैल रही पश्चिमी सभ्यता ने विरासत के हिंदू उत्तराधिकार कानून को बदल दिया, जिससे किसी हिंदू के ईसाई धर्म अपनाने पर भी वह अपनी पैतृक संपत्ति का उत्तराधिकारी बन सकता था।
- ईसाई मिशनरियों की बढ़ती गतिविधियों को संदेह और अविश्वास की नजर से देखा गया।

- सती प्रथा का उन्मूलन (1829, गवर्नर- विलियम बेंटिक) और विधवा पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता देना (1856, लॉर्ड डलहौज़ी), आदि को समाज के रीति-रिवाजों में अनुचित हस्तक्षेप माना गया।
- पश्चिमी शिक्षा प्रणाली की शुरुआत ने हिंदुओं और मुसलमानों की पारंपरिक/रूढ़िवादी मान्यताओं को सीधे चुनौती दी।
- सिपाहियों की अपनी धार्मिक या जातिगत शिकायतें भी थीं।

5. <u>सैन्य कारण:</u>
   - तात्कालिक कारण: चर्बी वाले कारतूसों का उपयोग।
   - सैन्य असंतोष का एक महत्वपूर्ण कारण सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम, 1856 था (लॉर्ड कैनिंग द्वारा स्थापित), जिसके तहत सिपाहियों को ज़रूरत पड़ने पर समुद्र पार जाना अनिवार्य कर दिया गया।
   - भारतीय और यूरोपीय सिपाहियों के बीच वेतन, पेंशन और पदोन्नति के मामले में भेदभाव था।भारतीय सिपाहीयों को सूबेदार के पद तक सीमित कर दिया गया था ।

6. <u>बाहरी घटनाओं का प्रभाव:</u>
   - 1857 का विद्रोह कुछ बाहरी घटनाओं के साथ हुआ, जिनमें अंग्रेजों को गंभीर नुकसान उठाना पड़ा था—पहला अफ़ग़ान युद्ध (1838-42), पंजाब युद्ध (1845-49) और क्रीमियन युद्ध (1854-56)। इन घटनाओं के स्पष्ट मनोवैज्ञानिक परिणाम थे।

7. <u>तात्कालिक कारण:</u>
   - चर्बी वाले कारतूसों का प्रकरण - नई एनफील्ड राइफल के कारतूसों पर चिकनाई लगी कागज़ की परत होती थी, जिसे राइफल में डालने से पहले दांतों से काटना पड़ता था। यह चिकनाई कुछ मामलों में गाय और सुअर की चर्बी से बनी होती थी।
   - इससे हिंदू और मुस्लिम सिपाही पूरी तरह से क्रोधित हो गए और उन्हें विश्वास हो गया कि सरकार जानबूझकर उनके धर्म को नष्ट करने की कोशिश कर रही है।

<u>विद्रोह का क्रम</u>

1. <u>सिपाही विद्रोह</u>
   - 29 मार्च, 1857: बैरकपुर में तैनात एक युवा सिपाही मंगल पांडे ने अकेले ही ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला करते हुए विद्रोह किया। उन्हें 8 अप्रैल को फांसी दे दी गई।
   - 24 अप्रैल: मेरठ में तैनात तीसरी नेटिव कैवेलरी के 90 सिपाहियों ने चर्बी वाले कारतूसों का उपयोग करने से इनकार कर दिया था ।
   - 10 मई: पूरी भारतीय रक्षक सेना ने विद्रोह कर दिया और दिल्ली की ओर कूच करने का फैसला किया। वे दिल्ली पहुंचे और वृद्ध बहादुर शाह ज़फ़र को भारत का सम्राट घोषित कर दिया।
   - जल्द ही बंगाल की पूरी सेना ने विद्रोह कर दिया, जो तीव्र गति से फैला । पूरा उत्तर और उत्तर-पश्चिम भारत अंग्रेजों के खिलाफ उठ खड़ा हुआ। मध्य भारत में भी, जहाँ शासक अंग्रेजों के प्रति वफादार रहे वहाँ सेना ने विद्रोह कर विद्रोहियों का साथ दिया। उदाहरण: इंदौर की सेना अपने शासक महाराजा होल्कार की अनिच्छा के बावजूद विद्रोह में शामिल हो गई।

2. जन विद्रोह

- विद्रोह के तुरंत बाद शहरी और ग्रामीण इलाकों में बगावत शुरू हो गई। जहाँ सरकारी खजाने को लूट लिया , बारूद गोदामों को तबाह कर दिया, बैरकों और न्यायालयों को जला दिया, और जेल के दरवाजे खोल दिए गए।
- इस विद्रोह में किसानों, कारीगरों, दुकानदारों, मजदूरों, जमींदारों, धार्मिक भिक्षुओं, पुजारियों आदि का व्यापक हिस्सा था।
- किसानों और छोटे जमींदारों ने साहूकारों और उन जमींदारों पर हमला किया जिन्होंने उन्हें जमीन से बेदखल कर दिया था। उन्होंने साहूकारों की खाता बही और ऋण अभिलेखों को नष्ट कर दिया।
- विद्रोह की सबसे उल्लेखनीय उपलब्धि हिंदू-मुस्लिम एकता थी।
- सभी सिपाहियों ने सम्राट बहादुर शाह ज़फ़र की सर्वोच्चता को स्वीकार किया और "दिल्ली चलो" का नारा दिया।

1857 के विद्रोह के क्षेत्रीय नेता

नेता का नाम	विद्रोह का स्थान	1857 के विद्रोह में निभाई गई भूमिका
नाना साहेब और तांत्या टोपे	कानपूर	➢ नाना साहेब, जो पेशवा बाजीराव द्वितीय के गोद लिए हुए बेटे थे, ने तांत्या टोपे की मदद से अंग्रेजों को कानपूर से खदेड़ दिया और नाना साहेब को पेशवा घोषित किया, जिन्होंने बहादुर शाह को भारत का सम्राट सवीकार किया ➢ तात्या टोपे महान योद्धा थे जिन्होंने रानी लक्ष्मी बाई को ग्वालियर पर कब्जा करने में मदद की।
बेगम हज़रत महल और बिरजिस कादिर	लखनऊ	➢ अवध की बेगम ने विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया और अपने बेटे बिरजिस कादिर को अवध का नवाब घोषित किया।
रानी लक्ष्मी बाई	झाँसी	➢ वह व्यपगत के सिद्धांत की नीति के खिलाफ थीं और अपने दत्तक पुत्र को झांसी की गद्दी पर बिठाने के लिए लड़ीं। ➢ मार्च, 1858 में अंग्रेजी सेना ने झाँसी पर हमला किया; लक्ष्मी बाई अपने बेटे के साथ क़िले से भागकर वह कालपी पहुँचीं, जहाँ उन्होंने तांत्या टोपे के साथ मिलकर ग्वालियर पर कब्जा किया।
कुंवर सिंह	आरा, बिहार	➢ उनके नेतृत्व में सैन्य और नागरिक विद्रोह पूरी तरह से जुड़े हुए थे, जिस के कारण अंग्रेज सबसे अधिक डरते थे। ➢ मार्च, 1858 में कुंवर सिंह ने आज़मगढ़ पर कब्जा कर लिया ।
शाह मल	बाघपत, उत्तर प्रदेश	➢ उन्होंने 84 गांवों (जिसे चौरासी देश कहा जाता है) के प्रधानों और किसानों को एकत्रित कर रात को एक गांव से दूसरे गांव तक मार्च किया और लोगों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह करने के लिए प्रेरित किया। ➢ उन्होंने “न्यायालय” (न्याय की ओवरी) की स्थापना की, जिसमें विवादों को निपटाकर और निर्णय दिए जाते थे।
मौलवी अहमदुल्ला	फैज़ाबाद	➢ वे अवध में विद्रोह फैलने के बाद एक प्रमुख नेता के रूप में उभरे।

प्रमुख शहीद क्रांतिकारी

विद्रोह के स्थान	नेता/नेतृत्वकर्ता
बैरकपुर	मंगल पांडे
दिल्ली	बहादुर शाह II, जनरल बख्त खान, हकीम अहसानुल्लाह (बहादुर शाह II के मुख्य सलाहकार)
इलाहाबाद और बनारस	मौलवी लियाकत अली
फैज़ाबाद	मौलवी अहमदुल्ला (उन्होंने इस विद्रोह को अंग्रेजों के विरूद्ध जिहाद घोषित किया)
बरेली	खान बहादुर खान
ग्वालियर/कानपुर	तात्या टोपे (इनका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग राव था। इनका मूल निवास येवला, महाराष्ट्र में था और बिठूर (कानपुर) में नाना साहब और मोरोपंत तांबे के संपर्क में आए।)

1857 के विद्रोह का दमन

- ब्रिटिश सेना ने लंबी और दमनात्मक लड़ाई के बाद 20 सितंबर, 1857 को दिल्ली का अधिग्रहण कर लिया। वृद्ध सम्राट बहादुर शाह ज़फ़र को बंदी बना लिया गया और रंगून (म्यांमार) निर्वासित कर दिया गया, जहाँ 1862 में उनकी मृत्यु हो गई।
- 1859 के अंत तक भारत में अंग्रेजी शासन पूरी तरह से पुनः स्थापित हो गया।
- विद्रोह विफल रहा लेकिन यह व्यर्थ नहीं गया। यह ब्रिटिश साम्राज्यवाद से स्वतंत्रता के लिए भारतीय लोगों का पहला महान संघर्ष था तथा इसने आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन के उदय का मार्ग प्रशस्त किया।

विद्रोह से जुड़े ब्रिटिश सेना अधिकारी

जनरल जॉन निकोलसन, विलियम हडसन, जेम्स आउट्रम	दिल्ली
जनरल नील	बनारस, इलाहाबाद और कानपुर
सर कॉलिन कैंपबेल	कानपुर और लखनऊ
हेनरी लॉरेंस	अवध के मुख्य आयुक्त -2 जुलाई, 1857 को लखनऊ में विद्रोहियों द्वारा ब्रिटिश निवास पर कब्ज़ा करने के दौरान मारे गए।
मेजर जनरल हैवलॉक	17 जुलाई, 1857 को विद्रोहियों (नाना साहब की सेना) को हराया। लखनऊ में उनकी मृत्यु हो गई।
विलियम टेलर और आई	आरा में विद्रोह को दबाया।
ह्यूग रोज़	झांसी में विद्रोह को दबाया।

विद्रोह की असफलता के कारण

1. योजना और संसाधनों की कमी
   - विद्रोहियों के पास कोई दूरदर्शी योजना नहीं थी।
   - अंग्रेजों के पास डाक, टेलीग्राम और रेलवे जैसे उन्नत संचार साधन थे, इसके विपरीत विद्रोहियों के पास ऐसे संसाधनों की कमी थी इसलिये उन्हें ऐसी सेवाएँ नहीं मिल सकीं।

2. भारतीयों में एकता का अभाव
   - 1857 का विद्रोह अधिकतर स्थानीय मुद्दों पर आधारित था, क्योंकि विभिन्न भारतीय नेताओं ने अपनी व्यक्तिगत समस्याओं के लिए संघर्ष किया।
   - बंगाल सेना के सिपाही विद्रोह कर रहे थे, जबकि पंजाब और दक्षिण भारत के कुछ सैनिक अंग्रेजों के पक्ष में विद्रोह दबाने में मदद कर रहे थे।
   - समाज के कुछ वर्ग विद्रोह के दौरान अंग्रेजों का समर्थन कर रहे थे।
   - विद्रोह का प्रसार केवल उत्तर भारत तक ही सीमित था।
3. शिक्षित भारतीयों का समर्थन न मिलना
   - आधुनिक शिक्षित भारतीयों ने इस विद्रोह का समर्थन नहीं किया क्योंकि उन्हें लगा कि यह विद्रोह पिछड़ेपन की ओर ले जाएगा।
   - शिक्षित मध्यम वर्ग ने गलतफहमी में यह मान लिया था कि अंग्रेज देश को आधुनिकीकरण की ओर ले जाएँगे।
4. नेताओं के बीच एकता का अभाव
   - मुख्य समस्या स्वयं विद्रोहियों के बीच एकता की कमी थी।
   - नेता एक-दूसरे के प्रति संदिग्ध और ईर्ष्यालु थे तथा अक्सर छोटे-मोटे झगड़ों में लिप्त रहते थे।
5. अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता
   - विद्रोहियों की हार का एक और प्रमुख कारण अंग्रेजों के पास उन्नत हथियारों की उपलबद्धता था ।
   - विद्रोहियों में अनुशासन और केंद्रीय कमान का अभाव था, जबकि अंग्रेजों को अनुशासित सैनिक, युद्ध सामग्री और धन की निरंतर आपूर्ति होती रही।

विद्रोह का प्रभाव

1857 के विद्रोह के विफल होने के बावजूद, इसने भारत में ब्रिटिश प्रशासन को गहरा झटका दिया। पुनः स्थापित ब्रिटिश शासन की संरचना और नीतियों में कई मामलों में बदलाव हुए।

1. ब्रिटिश क्राउन ने 1858 के एक अधिनियम (जिसे भारत की बेहतरी के लिए अधिनियम के रूप में जाना जाता है) के माध्यम से कंपनी पर अधिकार कर लिया।
2. सैन्य संगठन में बदलाव
   - बंगाल सेना में यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ा दी गई। बंगाल सेना में 1 यूरोपीय सैनिक पर 2 भारतीय सैनिक एवं बॉम्बे और मद्रास सेना में 1 यूरोपीय सैनिक पर 5 भारतीय सैनिक तय कर दिए ।
   - सेना की महत्वपूर्ण शाखाएँ जैसे तोपखाना विशेष रूप से यूरोपीय सैनिकों के नियंत्रण में कर दी गई।
   - सैनिकों में किसी भी प्रकार की राष्ट्रवादी भावना के विकास को रोकने के लिए जाति, समुदाय, धर्म और क्षेत्र (मार्शल रेस की अवधारणा) के आधार पर रेजिमेंटे बनाई गई।
3. फूट डालो और राज करो की नीति
   - जन साधारण के लिये भी "फूट डालो और राज करो" की नीति अपनाई गई, जिसके तहत सार्वजनिक नियुक्तियों और अन्य क्षेत्रों में मुसलमानों को कड़ी सजा दी गई और उनके साथ भेदभाव किया गया।
   - कालांतर मे इस नीति को बदलते हुए मुसलमानों का तुष्टीकरण शुरू कर दिया।
   - फूट डालो और राज करो की नीति ने भारत में सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया।

4. देशी रियासतों के प्रति नई नीति
   - विलय की नीति को अब त्याग दिया गया और शासकों को उत्तराधिकारी गोद लेने का अधिकार दिया गया।
   - जिन शासकों ने विद्रोह के दौरान ब्रिटिशों का समर्थन किया, यह उन शासकों को पुरस्कार के रूप में दिया गया अधिकार था
5. नए सहयोगियो का निर्धारण
   - अंग्रेजों ने देश में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए जमींदारों, राजकुमारों और जागीरदारों के साथ अपने संबंधों को बेहतर बनाया।
6. श्वेत विद्रोह
   - ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को सत्ता हस्तांतरण से कंपनी के अधीन कार्यरत यूरोपीय बलों के एक वर्ग ने इसका विरोध किया। इस असंतोष के परिणामस्वरूप कुछ अशांति पैदा हुई जिसे श्वेत विद्रोह कहा जाता है।

विद्रोह की प्रकृति

- डॉ. के. दत्ता 1857 के विद्रोह को विद्रोहियों के विभिन्न वर्गों के बीच सामंजस्य और उद्देश्य की एकता के अभाव से चिह्नित आंदोलन मानते हैं।
- वी.डी. सावरकर ने अपनी पुस्तक 'द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, 1857' में इसे " योजनाबद्ध राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम" के रूप में व्याख्यायित किया और इसे स्वतंत्रता का पहला युद्ध कहा।
- डॉ. एस.एन. सेन ने कहा कि यह सिपाही विद्रोह से अधिक था, लेकिन राष्ट्रीय आंदोलन से कम था।
- डॉ. आर.सी. मजूमदार इसे न तो प्रथम, न ही राष्ट्रीय, न ही स्वतंत्रता संग्राम मानते हैं।
- जवाहरलाल नेहरू ने 1857 के विद्रोह को मूलतः एक सामंतवादी विद्रोह माना, यद्यपि इसमें कुछ राष्ट्रवादी तत्व भी थे (डिस्कवरी ऑफ इंडिया)।
- टी.आर. होम्स- इन्होने इस विद्रोह को सभ्यता और बर्बरता के बीच संघर्ष माना ।
- जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने इस विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया।
- यह विद्रोह सांप्रदायिक एकता का एक महान प्रतीक था।

Unleash the topper in you

3 CHAPTER

ब्रिटिश शासन के तहत अर्थव्यवस्था

ब्रिटिश उपनिवेशवाद से पूर्व, भारत उच्च गुणवत्ता वाले सूती कपड़े, रेशम, मसाले और चावल का एक प्रमुख निर्यातक था। देश की अर्थव्यवस्था समृद्ध और शहरीकृत थी। 1764 में बक्सर के युद्ध में ब्रिटिश विजय के बाद, ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापार की अपेक्षा प्रत्यक्ष शासन की शुरूआत की। इसके परिणामस्वरूप औपनिवेशिक नीतियों के कारण भारत का औद्योगिक पतन हुआ, जिससे देश की अर्थव्यवस्था कमजोर हुई और विऔद्योगीकरण को बढ़ावा मिला।

कपड़ा उद्योग और व्यापार

- यूरोप में औद्योगीकरण के कारण भारतीय कपास, लिनन, रेशमी वस्त्र और ऊनी वस्तुओं का बाजार यूरोप, एशिया और अफ्रीका कमज़ोर हुआ।
- अब ब्रिटेन और भारत के बीच कपड़ा व्यापार की दिशा उलटी हो गई थी।
- इंग्लैंड से बड़ी मात्रा में मशीन-निर्मित उत्पादों के आयात से हस्तशिल्प उद्योगों को खतरा था क्योंकि ब्रिटिश सामान बहुत सस्ती कीमत पर बेचे जाते थे।
- विदेशी वस्तुओं को भारत में बिना किसी शुल्क के मुफ्त प्रवेश दिया जाता था, जबकि भारतीय निर्यात पर भारी कर लगाया जाता था और यहां तक कि ब्रिटेन में भारतीय वस्त्रों पर एक सुरक्षात्मक शुल्क लगाया जाता था।
- कपड़ों के निर्यातक से भारत कच्चे कपास का निर्यातक और ब्रिटिश कपड़ों का आयातक बन गया → बुनकरों के एक बड़े समुदाय के लिए बेरोजगारी → ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि मजदूरों के रूप में अपनी ही भूमि पर काम करने के लिए पलायन → ग्रामीण अर्थव्यवस्था और आजीविका पर दबाव बढ़ा।

विऔद्योगीकरण→ यह उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसमें भारतीय हथकरघा उद्योग को ब्रिटिश औद्योगिक उत्पादों के साथ असमान प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा।

पारंपरिक अर्थव्यवस्था का विघटन

- ब्रिटिश आर्थिक नीतियों ने भारत को ब्रिटिश अर्थव्यवस्था की जरूरतों के अनुसार चलने वाली एक औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में बदल दिया
  - ✓ पारंपरिक भारतीय अर्थव्यवस्था को बाधित कर दिया।
- ग्रामीण शिल्पों के क्रमिक विनाश ने ग्रामीण इलाकों में कृषि और घरेलू उद्योग के बीच संबंधो को तोड़ दिया और इस तरह आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विनाश में योगदान दिया।

कारीगर और शिल्पकार

- भारतीय पारंपरिक कला और शिल्प उद्योग को इन कारण से एक बड़ा झटका लगा:
- ब्रिटेन से सस्ते आयातित मशीन निर्मित माल के साथ हाथ से बने भारतीय सामानों की प्रतिस्पर्धा।
- 1813 ई. के बाद भारत पर एकतरफा मुक्त व्यापार की ब्रिटिश नीति भारतीय उद्योगों को नुकसान पहुंचाया।
- रेलवे के विकास ने ब्रिटिश माल की अधिक पहुंच सुनिश्चित की।
  - ✓ अमेरिकी लेखक डी.एच. बुकानन ने कहा था कि "आत्मनिर्भर और अलग-थलग रहने वाले गाँवों के कवच को स्टील रेल ने भेद दिया, और उनका जीवन रक्त धीरे-धीरे समाप्त हो गया।"

- कपास-बुनाई और कताई उद्योग सबसे ज्यादा प्रभावित हुए।
- रेशम और ऊनी वस्त्रों ने बेहतर प्रदर्शन नहीं किया और यही लोहा, मिट्टी के बर्तनों, कांच, कागज, धातु, बंदूकें, शिपिंग, तेल-दबाने, कमाना और रंगाई उद्योगों के साथ हुआ।
- कंपनी ने बंगाल के शिल्पकारों को अपना माल बाजार मूल्य से कम पर बेचने और प्रचलित मजदूरी से कम पर काम करने के लिए मजबूर किया, बड़ी संख्या में उन्हें अपने पुश्तैनी व्यवसायों को छोड़ने के लिए मजबूर किया।
- ब्रिटेन और यूरोप में भारतीय सामानों पर उच्च आयात शुल्क और अन्य प्रतिबंध लगाए गएI
- भारतीय राजघरानों और उनके दरबारों में धीरे-धीरे गिरावट के कारण ग्राहक आधार में कमी से हस्तशिल्प उद्योगों को हानि हुई।

19वीं सदी में भारत में कृषि का वाणिज्यीकरण

1. अमेरिकी गृहयुद्ध का प्रभाव (1861–1865): अमेरिकी गृहयुद्ध के दौरान ब्रिटेन को कपास की आपूर्ति बाधित होने से भारतीय कपास की मांग बढ़ गई। इससे कपास का उत्पादन और निर्यात तेजी से बढ़ा।
2. दक्कन क्षेत्र में वस्त्र उद्योग को बढ़ावा: ब्रिटिश कपड़ा उद्योग की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए दक्कन में कपास की खेती का भारी विस्तार हुआ, जिससे स्थानीय कृषि अर्थव्यवस्था बदल गई।
3. कपास निर्यात में भारत की प्रधानता: गृहयुद्ध के दौरान अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए, 1862 ई. तक भारत ने ब्रिटेन के कच्चे कपास का लगभग 90% आपूर्ति की।
4. आर्थिक असमानता: कपास की कृषि में अत्यधिक वृद्धि के बावजूद, किसानों (रैय्यतों) को साहूकारों से ऊंचे ब्याज पर कर्ज लेना पड़ा, जिससे वे कर्ज में डूब गए। इस तरह साहूकार और ब्रिटिश व्यापारी ज्यादा लाभ कमाते थे, जबकि किसान शोषित होते थे।
5. दक्कन के दंगे (1875): साहूकारों द्वारा आर्थिक शोषण और किसानों की वित्तीय परेशानियों ने दक्कन दंगों की शुरुआत की, जिसमें किसानों ने साहूकारों और ज़मींदारों के खिलाफ विद्रोह किया।

19वीं सदी में ब्रिटिशों द्वारा व्यावसायिक फसल खेती की मुख्य विशेषताएं

- व्यापारिक फसलों की शुरुआत: अंग्रजों ने अपने आर्थिक हितों को पूरा करने के लिए चाय, कॉफी, नील, अफीम, कपास, जूट, गन्ना और तिलहन जैसी व्यापारिक फसलों की खेती को बढ़ावा दिया।
- विशिष्ट फसलों के जरिए शोषण:
  - ✓ अफीम: अफीम का उपयोग चीन के साथ ब्रिटेन के व्यापार घाटे को संतुलित करने के लिए किया गया। अंग्रजों ने अफीम बाजार पर सख्त नियंत्रण रखा।
  - ✓ नील: किसानों को नील की खेती के लिए जबरन अनुबंधों में फंसाया गया, जिससे मिट्टी की उर्वरता में कमी आयी। बंगाल और बिहार में नील बागान मालिकों ने किसानों का शोषण किया। दीनबंधु मित्र के नाटक 'नील दर्पण' (1860) ने इस शोषण को उजागर किया।
- चाय बागान: चाय बागानों के मालिक बार-बार बदलते रहे, जबकि मजदूर कठिन परिस्थितियों में काम करने को मजबूर थे। यह ब्रिटिश उद्यानिकी नीतियों के शोषणकारी स्वभाव को दर्शाता है।
- किसानों और भूमि स्वामित्व पर प्रभाव: कृषि के व्यावसायीकरण ने भूमि स्वामित्व में बदलाव लाया, जिससे कई किसान भूमिहीन श्रमिक बन गए। वस्तुतः किसान व्यापारियों और बिचौलियों पर निर्भर हो गए, अतः उनका शोषण बढ़ा।
- खाद्य सुरक्षा में गिरावट: व्यावसायिक फसलों की अधिक खेती से खाद्यान्न उत्पादन में कमी आई, जिससे भोजन की कमी और उपनिवेशी भारत में अकाल की स्थिति उत्पन्न हुई।

उपरोक्त घटनाएँ दर्शाती हैं कि ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियों ने भारत की कृषि अर्थव्यवस्था को किस तरह परिवर्तित किया, जहाँ आर्थिक लाभ को प्राथमिकता दी गई और स्थानीय जनता की भलाई की उपेक्षा की गई।

ब्रिटिश भू-राजस्व नीतियाँ

- भारत में अंग्रेजों की आय का प्रमुख स्रोत भू-राजस्व था।
- भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान तीन प्रकार की भू-राजस्व नीतियाँ अस्तित्व में थीं:

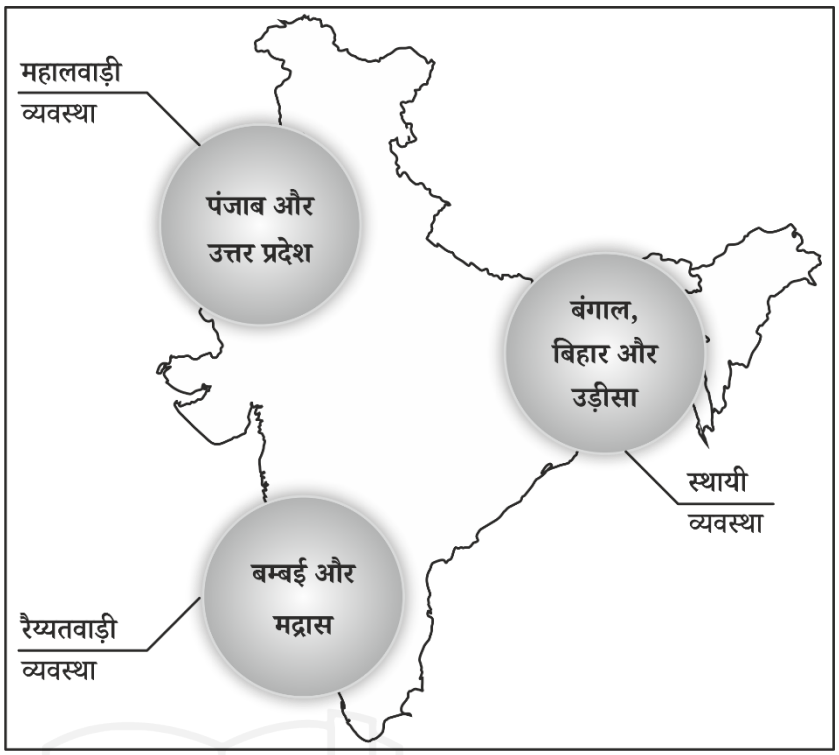

स्थायी बंदोबस्त (जमींदारी प्रथा) 1793

- लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1786 ई. में स्थायी बंदोबस्त प्रणाली का प्रस्ताव रखा।
- कॉर्नवालिस कोड-1793 ने कंपनी के सेवा कर्मियों को तीन शाखाओं में विभाजित किया: राजस्व, न्यायिक और वाणिज्यिक।
- इसे पहले बंगाल और बिहार में और बाद में मद्रास और वाराणसी के दक्षिणी जिलों में लागू किया गया।
- अंततः इसे सम्पूर्ण उत्तर भारत में विस्तारित किया गया।
- विशेषताएं
  - ✓ जमींदारों को भूमि के मालिकों के रूप में मान्यता दी गई थी (उत्तराधिकार के वंशानुगत अधिकार) ।
    - जमींदार अपनी इच्छानुसार जमीन बेच या हस्तांतरित कर सकते थे।
    - स्वामित्व तब तक रहेगा जब तक वे सरकार को उक्त तिथि पर निश्चित राजस्व का भुगतान करते हैं अन्यथा सूर्यास्त कानून लागू होगा।
- काश्तकार (रैयत) → काश्तकार; जमीन पर अधिकार नहीं
- अंग्रेजों के राजस्व का 10/11वां हिस्सा और 1/10वां हिस्सा जमींदारों के लिए था।
- जमींदार को काश्तकार को एक पट्टा देना होता था, जिसमें उसे दी गई भूमि का क्षेत्रफल और जमींदार को दिए जाने वाला लगान अंकित होता था।

> सूर्यास्त कानून
> 1794 में पेश किया गया, जिसके अनुसार यदि कोई जमींदार निश्चित तिथि के सूर्यास्त तक अपनी जमीन से राजस्व जमा करने में विफल रहता है, तो उसकी संपत्ति को जब्त और नीलाम कर दिया जाएगा।

रैय्यतवाड़ी बंदोबस्त

- 1820 ई. में थॉमस मुनरो (मद्रास के गवर्नर) द्वारा यह प्रणाली शुरू की गई, जो बारामहल जिले में कैप्टन अलेक्ज़ेंडर रीड द्वारा प्रशासित प्रणाली पर आधारित थी।
- मुख्यतः बॉम्बे, मद्रास, कुर्ग के कुछ भाग, असम आदि में संचालित है।
- विशेषताएं
  - ✓ सरकार को राजस्व संग्रह के लिए सीधे कृषक ('रैयत') से निपटने की अनुमति दी और किसानों को खेती के लिए नई भूमि देने या अधिग्रहण करने की स्वतंत्रता दी।

- ✓ किसानों का मूल्यांकन केवल उसी भूमि के लिए किया जाता था जिस पर वे खेती करते थे।
- ✓ पट्टेदार को किसी भी भूमि या भूमि के हिस्से को छोड़ने की अनुमति दी गई थी, जिसका पट्टा वो पूर्व सूचना देकर छोड़ सकता था और उस भूमि के लिए राजस्व देने से मुक्त हो सकता था।
- ✓ किसान = भूमि के स्वामी।
- ✓ स्वामित्व का अधिकार था, जमीन बेच सकता था, गिरवी रख सकता था या उपहार में दे सकता था।
- ✓ कर सीधे किसानों से सरकार द्वारा वसूल किया जाता था।
- ✓ शुष्क भूमि में दरें 50% और आर्द्रभूमि में 60% थीं।
- ✓ इसकी दरें अधिक थीं और उन्हें बढ़ाया भी जा सकता था।
- ✓ यदि किसान करों का भुगतान करने में विफल रहे, तो उन्हें सरकार द्वारा बेदखल कर दिया जाता।
- ✓ लेकिन, चूंकि उच्च करों का भुगतान केवल नकद में करना पड़ता था, इसलिए साहूकारों की समस्या उत्पन्न हो गयी थी→ जिससे किसानों पर ब्याज का बोझ बढ़ा।

महालवाड़ी व्यवस्था

- ➢ यह व्यवस्था 1822 में हॉल्ट मैकेंज़ी द्वारा लागू की गई ।
- ➢ इसे पंजाब, अवध और आगरा, उड़ीसा के कुछ भाग और मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम लागू किया गया।
- ➢ "महालवाड़ी" हिंदी शब्द महल = घर, जिला, पड़ोस; से निर्मित है।
- ➢ विशेषताएं
  - ✓ महल = गाँवों का समूह; छोटी-छोटी इकाइयों में बंटा गांव
  - ✓ राजस्व के भुगतान के लिए संयुक्त रूप से जिम्मेदार ग्राम समुदाय और जमींदार।
  - ✓ अनुशंसाओं, भूमि के सर्वेक्षण, भूमि में सम्बन्ध में अभिलेख तैयार करना, भू-राजस्व के निपटान, महलों से मांग और भू-राजस्व के संग्रह के लिए ग्राम प्रधान या लंबरदार पूरी तरह से जिम्मेदार थे।
  - ✓ राजस्व का राज्य हिस्सा = लगान के मूल्य का 66%।
  - ✓ समझौते पर 30 साल के लिए सहमति बनी थी।
  - ✓ यह एक तरह से संशोधित जमींदारी व्यवस्था थी जिसमे ग्राम प्रधान वस्तुतः जमींदार बन गया।
- ➢ हानि
  - ✓ गलत धारणाओं पर आधारित सर्वेक्षण → जोड़-तोड़ और भ्रष्टाचार।
  - ✓ कभी-कभी, कंपनी को राजस्व एकत्र करने में खर्च अधिक करना पड़ता। नतीजतन, प्रणाली को एक विफलता के रूप में माना गया।

तालुकदारी प्रणाली

- ➢ तालुकदार के अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग अर्थ थे, जैसे:
  - ✓ अवध - बड़ा जमींदार।
  - ✓ बंगाल - भूमि नियंत्रण और सामाजिक स्थिति के मामले में जमींदार के बाद।
- ➢ बड़े जमींदारों कई तालुक बन गये , जैसे, जंगलबुरी तालुक, मज़कुरी तालुक, शकीमी तालुक आदि।
- ➢ कुछ जमींदारी प्रबंधन की रणनीति के रूप में और कुछ जमींदारी से धन वसूलने के लिए एक राजकोषीय नीति उपाय के रूप में लायी गयी व्यवस्था।

मालगुजारी प्रणाली

- मध्य प्रांत में प्रचलित
- मालगुजार = मराठों के अधीन राजस्व किसान आम तौर पर प्रभावशाली और धनी व्यक्ति
- ब्रिटिश शासन के दौरान, उन्हें मालिकाना अधिकार दिए गए और उन्हें राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार ठहराया गया।
- यदि मुखिया कमजोर था या किसी अन्य कारण से, अधिकारियों द्वारा अपेक्षित राशि देने में असमर्थ था, या यदि कोई अदालत चाहती, तो बिना किसी हिचकिचाहट के एक किसान द्वारा मुखिया को बदल दिया जाता।
- किसान/प्रबंधक को पहले मुकद्दम/मुकद्दम कहा जाता था
- लेकिन 1855 के संक्षिप्त बंदोबस्त के नियम के तहत मालगुजार की उपाधि दी गई।
- मालगुजारों द्वारा नियुक्त लम्बरदार/सदर राजस्व लगाने वाला था।
- अन्य काश्तकार या तो पूर्ण अधिभोगी काश्तकार, अधिभोगी काश्तकार, उप-किरायेदार, रैयत-मलिक या पट्टेदार थे, जिन्हें विभिन्न आधारों पर उनकी जोत से बेदखल किया जा सकता था।
- मालगुजार (मालिक या सह-हिस्सेदार) के पास विशेष विवरण के तहत भूमि थी, अर्थात्, सर भूमि और खुदकाश्त भूमि।

भारतीय कृषि पर राजस्व प्रणाली का प्रभाव

- किसानों का शोषण और भूमिहीनता: असुरक्षित हस्तांतरण नीतियों के कारण किरायेदारों ने भूमि के अधिकार खो दिए। किराए की भारी मांग, अवैध देनदारी और 'बेगार' (जबरन मजदूरी) से किसान सरकार, ज़मींदारों और साहूकारों के तीन गुना शोषण का शिकार हुए।
- मध्यस्थों और दूरस्थ ज़मींदारों का उदय: पारंपरिक ज़मींदारों से भूमि संपत्ति व्यापारियों और साहूकारों के पास चली गई, जिससे गैर-हाज़िर ज़मींदारों का प्रचलन हुआ। बढ़े हुए मध्यस्थों ने किसानों का बोझ बढ़ा दिया, जबकि कृषि में कोई निवेश या कल्याण नहीं किया गया।
- भू-राजस्व पर ध्यान, उत्पादकता पर नहीं: ब्रिटिश और ज़मींदारों ने कृषि सुधारों की जगह किराए को अधिकतम करने पर ध्यान केंद्रित किया। इससे कृषि ठहराव की स्थिति में रही और किसान गरीबी में धकेल दिए गए।
- कृषि का व्यावसायीकरण: ब्रिटिश व्यापार मांगों के कारण खाद्यान्न की जगह व्यावसायिक फसलें उगाने पर जोर दिया गया। किसानों को इस प्रक्रिया में मजबूर किया गया, लेकिन इसका कोई अतिरिक्त लाभ नहीं मिला, जिससे गरीबी और अकाल बढ़े।
- भूमि विखंडन और निवेश की कमी: उप-इजारेदारी ने भूमि को खंडित कर दिया, जिससे आधुनिक कृषि सुधार रुक गए। सरकार या ज़मींदारों द्वारा न्यूनतम निवेश ने उत्पादकता को और खराब किया और कृषि संकट को गहरा दिया।

व्यापार एवं वाणिज्य

- निदेशक मंडल (Court of director) ने इंग्लैंड और भारत के बीच व्यापार में भारतीय जहाजों के उपयोग का विरोध किया → भारत से ब्रिटेन को होने वाले निर्यात में बाधा डाली + भारतीय जहाजरानी उद्योग पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा।
- अंग्रेजों द्वारा भारत में लौह उद्योगों के विकास की अवहेलना।
- ब्रिटिश निर्माताओं को कच्चे माल की आपूर्ति के लिए कृषि का व्यावसायीकरण; परिणामस्वरूप:-
  - ✓ विशेष रूप से अकाल के दौरान खाद्यान्न की कमी।
  - ✓ सस्ते ब्रिटिश सामानों ने भारतीय कुटीर और हथकरघा उद्योग को नष्ट कर दिया।

विदेशी व्यापार

ब्रिटिश शासन के दौरान	विवरण
ब्रिटिश → विदेशी व्यापार पर एकाधिकार	➢ ब्रिटेन ने भारत के आयात और निर्यात पर नियंत्रण किया। ➢ भारत के विदेशी व्यापार का आधा हिस्सा केवल ब्रिटेन के लिए आरक्षित था, और बाकी का व्यापार श्रीलंका, चीन और फारस (ईरान) के साथ होता था। ➢ 1869 में स्वेज नहर की शुरुआत ने भारत के विदेशी व्यापार पर ब्रिटिश अधिकार को और बढ़ा दिया।
कच्चे माल का निर्यातक और निर्मित वस्तुओं का आयातक	➢ भारत को ब्रिटिश निर्माताओं के लिए सभी कच्चे माल का निर्यात करना पड़ता था और सस्ते निर्मित उत्पाद भारतीय बाजारों में आयात किए जाते थे।
ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय धन की निकासी	➢ औपनिवेशिक काल के दौरान भारत के विदेशी व्यापार ने अधिक निर्यात के कारण अधिशेष उत्पन्न किया, लेकिन इससे भारत को कोई लाभ नहीं मिला। ➢ इसके बजाय, इस अधिशेष का उपयोग निम्नलिखित के भुगतान के लिए किया गया: ✓ ब्रिटेन में उपनिवेशीय सरकार द्वारा स्थापित कार्यालयों के व्यय। ✓ ब्रिटिश सरकार के युद्ध व्यय । ✓ अदृश्य वस्तुओं के आयात, आदि।

धन की निकासी सिद्धांत

➢ सिद्धांत और उत्पत्ति-
- ✓ धन निकासी सिद्धांत (Drain of Wealth Theory) की अवधारणा वर्ष 1867 में दादाभाई नौरोजी ने प्रस्तुत की। उन्होंने तर्क दिया कि भारत की गरीबी का कारण आंतरिक कारक नहीं बल्कि औपनिवेशिक शोषण है। उन्होंने बताया कि भारत को बिना मुआवजा दिए धन ब्रिटेन भेजा गया, जिससे भारत के विकास के लिए आवश्यक संसाधन छिन गए।
- ✓ नौरोजी ने अपनी पुस्तक 'पॉवर्टी एंड अन-ब्रिटिश रूल इन इंडिया' में इस सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या की, और कहा कि भारत का एक-चौथाई राजस्व हर वर्ष ब्रिटेन को भेजा जाता था।

➢ मुख्य योगदानकर्ता
- ✓ आर.सी. दत्त ने अपनी पुस्तक 'इकोनोमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया' (1901) में अत्यधिक कराधान और भू-राजस्व नीतियों की आलोचना की।
- ✓ एम.जी. रानाडे ने 'भारतीय अर्थशास्त्र पर निबंध' (1899) में औद्योगीकरण की आवश्यकता पर जोर दिया, जिससे आर्थिक ठहराव को रोका जा सके।
- ✓ अन्य आलोचकों में जी.वी. जोशी, जी.के. गोखले, और पी.सी. रे ने बताया कि कैसे औपनिवेशिक नीतियों ने भारतीय उद्योगों और कृषि को प्रभावित किया।

➢ धन निकासी के रूप
- ✓ कंपनी प्रेषण: ब्रिटिश अधिकारियों और प्रशासकों का वेतन, पेंशन और "गृह व्यय"।
- ✓ निजी हस्तांतरण: ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा अर्जित संपत्ति, जैसे लूट, रिश्वत और मुनाफा, इंग्लैंड भेजा गया।
- ✓ सेवाओं के भुगतान: ब्रिटिश बैंकों, बीमा कंपनियों, और शिपिंग कंपनियों को सेवाओं के लिए धन भेजा गया।
- ✓ क्षेत्रीय विस्तार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक राजस्व और भारतीय वस्तुओं के निर्यात से मुनाफा कमाने में सहायता की।

- धन निकासी के परिणाम
  - ✓ आर्थिक निर्धनता: समाज के सभी वर्ग, विशेष रूप से किसान, भारी कराधान के कारण पीड़ित हुए।
  - ✓ विऔद्योगीकरण: भारत की पूंजी का उपयोग ब्रिटेन के औद्योगिक क्रांति को वित्तपोषित करने में किया गया, जिससे भारत का औद्योगिकीकरण रुक गया।
  - ✓ कुटीर उद्योगों का पतन: ब्रिटिश नीतियों, जैसे मुक्त व्यापार और "लैसेज़-फेयर"(अहस्तक्षेप) ने भारत के पारंपरिक उद्योगों को नष्ट कर दिया और इसे औद्योगिक ब्रिटेन के लिए एक कृषि अर्थव्यवस्था बना दिया।
- राष्ट्रीय प्रतिक्रिया
  - ✓ उपनिवेशवाद की आर्थिक समीक्षा ने ब्रिटिश "कल्याणकारी" चरित्र को धूमिल दिया और उनके शोषणकारी नीतियों को उजागर किया।
  - ✓ इस सिद्धांत ने राष्ट्रीय नेताओं को स्वराज (स्व-शासन) की मांग करने के लिए प्रेरित किया, जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम की नींव बनी।
  - ✓ इसने आर्थिक शोषण और राजनीतिक अधीनता के बीच संबंध को रेखांकित किया, जिससे भारतीय एकजुट होकर औपनिवेशिक शासन का विरोध कर सके।
  - ✓ धन निकासी सिद्धांत यह बताता है कि कैसे ब्रिटिश आर्थिक नीतियों ने भारत को व्यवस्थित रूप से निर्धन बनाया और स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित किया।

ब्रिटिश शासन के दौरान आर्थिक विकास

उद्योग

- भारत अपने औद्योगिक उत्पादों के लिए काफी प्रसिद्ध था।
- अहमदाबाद की ढाका मलमल, धोती और दुपट्टा, लखनऊ की चिन्ट्ज़, मदुरै की साड़ियाँ आदि भारत में प्रसिद्ध शहरी हस्तशिल्प उद्योग थे।
- इसके अलावा, बंगाल, पूना, अहमदाबाद आदि में उत्पादित रेशमी कपड़े भी काफी प्रसिद्ध थे।
- कश्मीर और पंजाब के कुछ हिस्सों में उत्पादित कश्मीरी शॉल यूरोप में भी काफी प्रसिद्ध थे।
- भारत में फिर से धातु उद्योगों की एक अच्छी संख्या फली-फूली, जिसमें बनारस, नासिक, पूना, हैदराबाद, तंजौर, विशाखापत्तनम आदि में स्थापित पीतल, तांबा और बेल-धातु उद्योग शामिल हैं।
- इन उद्योगों के अलावा, कंपनी के आगमन के समय भारत में मौजूद अन्य उद्योगों में पत्थर की नक्काशी, सोने और चांदी के धागे का काम, आभूषण, चंदन की लकड़ी का काम, संगमरमर का काम, कांच की चूड़ियाँ बनाना, चमड़े का काम, लोहे की फोर्जिंग, जहाज निर्माण आदि शामिल थे।
- 18वीं शताब्दी के अंत में और उसके बाद, उपरोक्त अधिकांश हस्तशिल्प उद्योगों का तेजी से पतन हुआ।
- पतन का कारण औद्योगिक क्रांति के बाद इंग्लैंड में उत्पादित कारखाने-निर्मित सामानों के साथ भारतीय हस्तशिल्प उद्योगों द्वारा सामना की जाने वाली बढ़ती प्रतिस्पर्धा थी।
- अपने उद्योगों और व्यापार के संबंध में अंग्रेजों द्वारा अपनाई गई नीतियां भी भारतीय उद्योगों के पतन के लिए जिम्मेदार थी।
- भारत को संयुक्त कृषि और निर्माण के देश से जबरन ब्रिटिश विनिर्माण पूंजीवाद के कृषि उपनिवेश में बदल दिया गया था।
- ब्रिटिश शासन ने कच्चे माल के उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए और अपने औद्योगिक तैयार माल की बिक्री के लिए भारत में एक संभावित बाजार बनाने के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को एक प्राथमिक उत्पादक देश के रूप में बदल दिया।
- ब्रिटिश पूंजीपतियों ने भौगोलिक कारणों से धीरे-धीरे भारत में चाय, जूट और कॉफी उद्योग का विकास किया और अंततः भारतीय मजदूरों का बड़े पैमाने पर शोषण किया।

परिवहन

- सामरिक, प्रशासनिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टि से परिवहन और संचार के विकास को काफी महत्वपूर्ण माना गया है।
- जब अंग्रेज भारत आए तो भारत में परिवहन और संचार व्यवस्था तुलनात्मक रूप से पिछड़ी हुई थी।

सड़क परिवहन

- भारत में सड़क संचार 19वीं सदी के शुरुआती दौर में बेहद अविकसित थे।
- मुगल सम्राटों द्वारा केवल कुछ ट्रंक सड़कों का विकास किया गया था।
- सभी मौसम वाली सड़कों के अभाव के कारण, गाँव पूरी तरह से कट गए थे और मानसून के दौरान बाकी क्षेत्रों से अलग-थलग रहे।
- हालाँकि अंग्रेजों ने भारत पर अपनी विजय के शुरुआती दौर में कुछ सड़कों का निर्माण किया था, लेकिन उनमें से अधिकांश को देश पर विजय प्राप्त करने के बाद छोड़ दिया गया था।
- 1836 में, कंपनी ने डाक संचार शुरू करने के लिए कुछ पहल की और इस तरह कलकत्ता-दिल्ली सड़क का निर्माण शुरू किया।
- 1842 में फिर से कलकत्ता और बॉम्बे और बॉम्बे और आगरा को सड़कों से जोड़ा गया।
- लॉर्ड डलहौजी के शासन काल में ही 1850 में केंद्रीय लोक निर्माण विभाग की स्थापना हुई थी और देश के विभिन्न हिस्सों में सड़कों के निर्माण के लिए वास्तविक पहल की गई थी।
- कंपनी ने सड़क विकास की जिम्मेदारी लोक निर्माण विभाग के बजाय प्रांतीय सैन्य बोर्डों को सौंपकर सड़क विकास की उपेक्षा की।
- अधिक सड़कों के निर्माण की बढ़ती आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए और सड़क विकास के प्रश्न की जांच करने के लिए, भारत सरकार ने 1827 में एक सड़क विकास समिति नियुक्त की।
- समिति ने सुझाव दिया कि ग्रांड ट्रंक सड़कों का रखरखाव केंद्र सरकार द्वारा किया जाए और शेष सड़कों का रखरखाव प्रांतीय सरकार और स्थानीय निकायों द्वारा किया जाए।
- समिति ने सड़कों के निर्माण के लिए प्रांतीय सरकार को अनुदान प्रदान करने के लिए पेट्रोल के प्रति गैलन 2 आने का अतिरिक्त शुल्क लगाते हुए 'रोड फंड' नामक एक अलग फंड की भी सिफारिश की।
- तदनुसार, भारत सरकार ने 1934 में स्थायी आधार पर एक रोड फंड बनाया।
- 1880 के बाद देश में और 1943 तक ब्रिटिश शासन के तहत व्यापक सड़क निर्माण हुआ।

रेलवे

- रेलवे के विकास ने ब्रिटिश काल के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
- इंग्लैंड में रेलवे की शुरुआत 19वीं सदी की पहली तिमाही के दौरान हुई थी और यात्रियों को ले जाने वाली पहली रेलवे लाइन 1825 में इंग्लैंड में सेवा के लिए खोली गई थी।
- 1832 में भारत में रेलवे निर्माण का पहला प्रस्ताव रखा गया था।
- 1844-45 में पूर्वी और दक्षिण-पश्चिम भारत में रेलवे लाइनों के निर्माण के लिए भारत में कई सर्वेक्षण किए गए।
- 1849 में, ईआईसी और ग्रेट ब्रिटेन पेनिनसुला रेलवे कंपनी ने बॉम्बे के बंदरगाह और बरार के कपास उगाने वाले ट्रैक के बीच एक प्रायोगिक रेलवे लाइन के निर्माण के लिए एक अनुबंध किया।